presented in March, a copy of which is being circulated with the Budget papers, along with a Supplement explaining the subsequent changes.

In presenting these budget proposals to the House, I would conclude with the expression of my confidence that in debating these proposals the House will bear in mind the compelling economic necessities of the situation and the vital importance of avoiding an overdraft on the limited resources of Government already being strained to the utmost on other accounts.

14.40 hrs.

GOVERNMENT (LIABILITY IN TORT) BILL*

The Minister of Parliamentary Affairs and Communications (Dr. Ram Subhag Singh): On behalf of Mr. Govinda Menon, I beg to move for leave to introduce a Bill to define and amend the law with respect to the liability of the Government in tort and to provide for certain matters conneced therewith.

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to define and amend the law with respect to the liability of the Government in tort and to provide for certain matters connected therewith."

The motion was adopted.

Dr. Ram Subhag Singh: I introduce the Bill.

14.41 hrs.

MOTION RE: REPORT OF UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION, 1964-65.

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): I beg to move:

"That this House takes note of the Fifteenth Report of the Union Public Service Commission for the period 1st April, 1964 to 31st March, 1965, together with the Government's Memorandum thereon, laid on the Table of the Third Lok Sabha on the 2nd March, 1966."

Shri Kanwarlal Gupta (Delhi Sadar): I want to raise a point of order on this.

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है । मैं आपका ध्यान आर्टिकल 323 की तरफ दिलाना चाहता हूं । इस में स्पष्ट रूप में लिखा है —

"It shall be the duty of the Union Commission to present annually to the President a report as to the work done by the Commission and on receipt of such report the President shall cause a copy thereof together with a memorandum explaining, as respects the cases, if any, where the advice of the Commission was not accepted, the reasons for such non-acceptance to be laid before each House of Parliament."

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर यह है कि यह ठीक है कि टैकनीकली यह रिपोर्ट चाहे हाउस में 1965 में रख दी गई हो, लेकिन दो-सवा दो वर्ष में जहां तक मेरी इन्फर्मेशन है, इस पर बहस नहीं हो सकी । चाहे लैटर आफ दी ला को फौलो किया गया हो, लेकिन स्प्रिट में वायोलेशन हुआ है और इस बारे में जो पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस है, उस को इगनोर किया गया है ।

इस रिपोर्ट के हर साल रखने का आईडिया यह है कि मेम्बर उस के बारे में अपने विचार रख सकें, उस में जो कुछ लिखा हुआ है उस को सुनने के बाद उसकी इम्प्लीमेंट के बारे में अपने विचार रख सकें, इसी आईडिये के साथ इस रिपोर्ट को हर साल रखने का प्रोवीजन कांस्टीट्यूशन में किया गया था,

*Published in Gazette of India Extraordinary Part II, section 2, dated 23rd May, 1967.

[Shri Kanwarlal Gupta]

लेकिन अगर उस पर डिस्कशन नहीं होता है, तो उस का सारा महत्व खत्म हो जाता है । यह सरकार की डिम्मेदारी है कि रिपोर्ट के यहां पर रख जाने के बाद, उस पर डिस्कशन कराये । यह पहला मौका नहीं है जब कि इस तरह की गल्ती सरकार कर रही है, सरकार वास्तव में इस को बहुत लाइटली ले रही है । सन 1962-63 की जो रिपोर्ट थी, उस पर भी दो साल के बाद हाउस में डिस्कशन हुआ था इस लिये इस प्रकार की प्रेक्टिस पहले से चली आ रही है।

इसलिये मैं आपके जरिये सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर आप सही भावनों में कान्स्टीचूशन को फौलो करना चाहते हैं तथा जिस उद्देश्य से कि यह धारा कान्स्टीचूशन में बनाई गई थी, उस को पूरा करने के लिये आप सरकार से कहिये कि हम लोगों को यह फीलिंग है कि उसी साल में इस रिपोर्ट पर बहस होनी चाहिये । दो-ढाई साल के बाद इस तरह से रिपोर्ट आयेगी, तो इस का कोई मतलब नहीं है, बल्कि यह एक सिरदर्द की चीज रह जायगी, मरे मुर्दे को उखाड़ना होगा, इस का और कोई लाभ न होगा । इस लिये आप सरकार से कहें कि इस तरह की गलत चीज आइन्दा न हो ।

Shri A. B. Vajpayee (Bairampur) rose—

Shri Vidya Charan Shukla: After my explanation, it may not necessary for the hon. Member to say anything. If the hon. Member had been a little patient, it might not have been necessary to raise this point.

We laid this report on the Table of the House on 2nd March, 1966. Immediately thereafter, after about 14 days, we gave notice of a motion for discussion of the report in the House, but unfortunately, the House could not find time.

Shri Kanwar Lal Gupta: This is Government business.

Shri Vidya Charan Shukla: After that two times we gave two more notices for discussion of this report, but to our ill-luck the House could not find time. Our notices are pending, but there was no time fixed for discussion. This Government motion has been pending for about one year and 9 months. So, it is not our fault that this report has not been discussed.

Shri Kanwar Lal Gupta: This is Government business. The Government should see to it that the report is discussed.

Shri Vidya Charan Shukla: The reasons because of which many important matters could not be discussed in this House are well known to the House, I need not go into them. We know under what strain this has been going on. The Business Advisory Committee has been allotting time for discussion of various important matters, but may be more important things intervened and the House in its wisdom did not find time to discuss this report, but as far as the Government is concerned, we took the prompt step of moving a motion for its consideration not only once, but thrice. So, it is not the fault of the Government at all.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, इस के लिये समय नहीं मिला, यह किसकी गलती है । बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को दोष देना ठीक नहीं है । सरकार हमारे सामने जो बिजनेस लाती है, उस के लिये समय तय करना बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का काम है । इस पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट पर जब मैं राज्य सभा में था, 4 मार्च, 1966 को वहां बहस हुई थी, उस के नवा साल बाद अब इस पर लोक सभा में बहस हो रही है—आखिर इस में किसी न किसी की गलती जरूर है ।

अगर सरकार समय निकालना चाहती, तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी उसे समय देती। मंत्री महोदय को मानना चाहिये कि गल्ती हुई है और आगे से ऐसी गल्ती नहीं होगी।

श्री कुंवर लाल गुप्त : सरकार यह एश्योरेन्स दे कि आइन्दा से इस प्रकार का दो-ढाई साल का विलम्ब नहीं होगा।

Mr. Deputy-Speaker: The Minister already came before the House with a motion, but for want of time it could not be taken up. What is to be done?

Shri Kanwar Lal Gupta: It is Government business. Government should come before the Business Advisory Committee to allot time for it. It is not the fault of the Business Advisory Committee.

श्री कमलनयन बजाज (वर्धा) : उपाध्यक्ष महोदय यह सवाल जो कि पाइन्ट आफ आर्डर के रूप में अपोजीशन की तरफ से मूव हुआ है इस बारे में बराबर जवाब दिया गया है। इस के बारे में एक-दो बातें और भी आ जाती हैं। एक बात तो यह आ जाती है कि अपोजीशन भी जितनी एलर्ट रहनी चाहिये उतनी प्रापर्ली नहीं रही। उन के ध्यान में भी दो-सवा दो साल के बाद यह बात आई कि फलानी बात पर चर्चा होनी थी वह नहीं हुई। जहां तक सरकार का सम्बन्ध है उनकी तरफ से एक दफा नहीं दो दफा तीन दफा इस को यहां पर रखने की कोशिश की गई लेकिन अपोजीशन को यह भी ध्यान रखना चाहिये कि कितना समय यहां पर फजूल की बातों के अन्दर खराब कर देते हैं रोज घन्टों के घन्टों फजूल में बने गये.....व्यवधान....

जब आप बोलते हैं तो हम दखल नहीं देते हैं। मेरे बोलने के बाद यदि आप बोलना चाहें तो बोल सकते हैं।

श्री रामसेवक यादव (बाराबंकी) : आप समय की बात कह रहे हैं फजूल का समय चला जाता है मुझे इस पर एतराज है।

श्री कमलनयन बजाज : आप बाद में बोल लीजियेगा। जब आपकी बात पर हमें एतराज होता है तो हम आपके बीच में नहीं बोलते हैं हमारी सभ्यता का इस तरह से दुरुपयोग करें यह ठीक नहीं है। आपको जो कुछ जवाब देना हो बाद में दें।

जब सरकार समय निर्धारित करती है उस में जितना समय पीछे लगा है उसी के हिसाब से निर्धारित करती है। लेकिन आखिर में जब समय नहीं रहता है और अपोजीशन रोज घन्टों के घन्टों अन्य बातों में समय निकाल देती है तब बाद में कुछ ऐसे विषयों को छोड़ देना पड़ता है जो कि ज्यादा इम्पार्टेन्ट नहीं माने जाते। मैं चाहता हूं कि इन बातों पर गौर होना चाहिये।

Shri Tenneti Viswanatham (Visakhapatnam): I do not follow Hindi, but if I heard the translation correctly, the hon. friend says that we on this side are accustomed to wasting time. It is a very objectionable statement.

Mr. Deputy-Speaker: As I have already explained, he says extraneous matters were raised which took a lot of time.

Shri Tenneti Viswanatham: Matters are raised and the Chair allows them and no objection is taken at that time. Is it proper for the respectable friend sitting to my front now and say that we are wasting the time or that extraneous matters are raised. It is wrong.

Mr. Deputy-Speaker: He never intended to say that there was any waste of time.

Shri Tenneti Viswanatham: Coming to the main point of the Minister, it is that it is not the fault of the Government if the report was not brought for discussion. But the fact is that

[Shri Tenneti Viswanatham]

it is the fault of the Government. If they cannot find time, they must be extended the time; there is no use saying that they will sit up to a particular hour only. It is constitutionally binding upon them to bring this matter up for discussion here; they should not say that more important matters were taken up; these are as important as any other matters. It is certainly the fault of the Government and let him not repeat this again.

श्री रामसेवक यादव : अध्यक्ष महोदय मंत्री महोदय ने इस यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन की 15वीं रिपोर्ट पर हाउस में अभी तक डिस्कशन न हो पाने के बारे में सफाई दी कि इस में सरकार का दोष नहीं था और उस से ऐसा लगता है जैसे विरोधियों का दोष हो। मैं चाहता हूं कि सिर्फ यह पब्लिक सर्विस कमिशन की रिपोर्ट के डिस्कशन में ही देरी नहीं हुई है बल्कि और भी बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं और जो कि गृह मंत्रालय से ही सम्बन्धित हैं जैसे कि पिछड़े वर्ग आयोग का प्रतिवेदन है जो कि कई वर्षों से बगैर डिस्कस हुए पड़ा है। मैं इस सिलसिले में यह भी कहना चाहता हूं कि विरोधियों की जो जिम्मेदारी थी उस को उन के द्वारा निभाया गया है जैसे कि एक पुराने आयोग का प्रतिवेदन था जिसको कि बार बार कोशिश करने के बाद उस पर दूसरे ढंग से किसी सदस्य के प्रतिवेदन पर होकर उस पर होकर उस पर चर्चा हुई लेकिन सरकार की तरफ से उस पर चर्चा नहीं हुई। अब यदि आवश्यक हो तो हाउस के काम का समय बढ़ाया जा सकता है और भी कोई उसके लिए तरीका निकाला जा सकता है लेकिन सरकार इस तरह से अपनी जिम्मेदारी से भागे यह ठीक नहीं है और मैं चाहूंगा कि और भी गृह मंत्रालय के प्रतिवेदन जो कि इस तरह से बगैर डिस्कशन के पड़े हुए हैं उन के ऊपर जल्दी से सरकार डिस्कशन कराये।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : जब अभी आगे पार्टी लीडर्स की मीटिंग हुई थी तो उस में यह विचार प्रकट किया गया था कि अब जब कि पार्लियामेंट का काम बढ़ गया है तो हाउस के वर्किंग आवर्स को भी बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि यह देखने में आ रहा है कि समय कम निर्धारित होने के कारण पब्लिक इंटरेस्ट की बहुत सी महत्वपूर्ण बातें जो कि यहां हाउस में आनी चाहिएं वह भी नहीं उठ पाती हैं। इसलिए गवर्नमेंट का यह काम है कि वह इस ओर देखे और अगर काम का समय थोड़ा हो तो काम के घंटे अधिक बढ़ाये जायें क्योंकि जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर पार्लियामेंट में डिस्कशन होना चाहिए।

श्री कंवर लाल गुप्त : कुछ तो मंत्री जी की तरफ से आना चाहिए। आयन्दा इस तरह से देरी न की जायगी इस का तो उन की तरफ से कोई एश्योरेंस आना चाहिए।

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : कसूर तो अपोजीशन वालों का है और जिम्मेदारी उस के लिए मंत्री जी के ऊपर थोपी जाती है। हाउस का टाइम किस तरह से वेस्ट होता है उस की मैं एक मिसाल देता हूं। स्वेतलाना के बारे में यहां विपक्षी दल के कुछ लोगों ने सवाल उठाया और दो दिन तक लगातार स्वेतलाना पर हाउस में डिस्कशन हुआ और इस तरह से हाउस के दो दिन वेस्ट हुए। मैं किसी विशेष पर इसके लिए आक्षेप नहीं करता लेकिन मैं समझता हूं कि हर एक माननीय सदस्य इस हाउस का महसूस करता होगा कि इस तरह से कुछ लोगों द्वारा इस स्वेतलाना के मामले को उठा कर हाउस का समय बर्बाद किया गया। यह दो दिन का समय बचाया जा सकता था ... (व्यवधान) इस तरह से आप लोग मुझे सही बात कहने से बंद नहीं कर सकते। मुझे यह कहना पड़ता है कि इस तरह के गैर जरूरी मामले यहां पर उठा कर इस हाउस का कीमती समय

ये लोग खराब करते हैं जोकि बचाया जा सकता है.....(व्यवधान) श्री राम सेवक यादव उनके साथी हाउस का समय खराब करते हैं (व्यवधान)

श्री रामसेवक यादव : हम समय बिलकुल खराब नहीं करते लेकिन जनहित में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उन्हें हम हाउस में उठाना अपना कर्तव्य समझते हैं ।

श्री रणवीर सिंह : समय आप नहीं बर्बाद करते तो और क्या करते हैं ? अब आध घंटा इसी में लगा दिया ।

श्री रामसेवक यादव : जो भी यहां हाउस में कार्यवाही चलती है चाहे वह काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा हो चाहे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे में चर्चा हो अथवा अन्य किसी विषय पर यहां पर चर्चा हो वह तभी हो पाती है जबकि सभापति महोदय द्वारा उस की इजाजत दी जाती है अथवा बिजनैस एडवाइजरी कमेटी द्वारा उस के बारे में हाउस में डिस्कस होने के लिए फैसला होता है । ऐसी हालत में किसी माननीय सदस्य के लिए क्या हाउस में इस तरह से खड़े होकर किसी चर्चा का हवाला देते हुए यह कहना उचित होगा कि उस पर चर्चा करके हाउस का समय बर्बाद किया गया ? मैं चाहूंगा कि इस तरह की बातें मैम्बरों को यहां नहीं कह देनी चाहिएं ।

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Member should realise that whatever was discussed was discussed with the permission of the Chair. He should not criticise the Chair.

The Minister of Parliamentary Affairs and Communications (Dr. Ram Subhag Singh): We have noted the suggestions that have been given by the hon. Members for our future guidance.

Shri Vidya Charan Shukla: The Constitution lays down that the annual report of the UPSC shall be laid before both Houses of Parliament along with a memorandum explaining the reasons where the advice of the Commission had not been accepted by the Government. It is unfortunate that we could not have a full-fledged discussion earlier than this day. As I said earlier, it is our established convention that save in very exceptional circumstances, Government always accepts the advice of the UPSC in regard to appointments where the Commission is consulted. Unless in the opinion of the Minister concerned exceptional circumstances warrant a departure in public interest, the Commission's recommendations are not generally departed from. Even in such cases, we have to refer them back again to the Commission with our reasons for differing from their views. Then the Commission considers the matter again and they send us back their recommendations. After reconsideration of those views, Government may accept the recommendation. If the Government is still unable to accept it, the Minister concerned has to take the matter to the appointments committee of the Cabinet which gives the final order about these matters. In cases other than appointments or promotions, whenever any Ministry considers it desirable not to accept the UPSC recommendations, they have to refer the matter to the Home Ministry giving valid reasons. I am mentioning all this to show that we have laid down a very elaborate process to see that there is no light hearted difference from the UPSC as far as the Government working is concerned. We are very anxious that most serious consideration should be given to such questions where to Government find it difficult to accept the recommendations of the UPSC.

15 hrs.

I will give some figures relating to the past few years when we found it difficult to accept the recommendations, and those figures will amply show to hon. Members that we attach the highest importance in respect of the advice tendered to us by the

[Shri Vidya Charan Shukla]

UPSC. In the year 1962-63, 12,600 cases were referred to the Commission for their advice and there was only one case in which we found it difficult to accept their advice. In the year 1963-64, 14.425 cases were referred to the Commission and we accepted their advice in all the cases. In 1964-65, 12,900 cases were referred to the UPSC and we accepted their advice in every case except one. This only goes to show that we have been trying to respect all the advice and recommendations that the UPSC had been giving to the Government; and this is in keeping with spirit in which our Constitution created this body for regulating the public services in our country.

There are certain other matters which have been referred to in this report and I am sure the hon. Members would raise some points and give their valuable advice on those points. But I would like to refer to a few of those points so that the Members may give us the benefit of their opinion and their advice on those important matters. One of the matters which I want particularly to mention here is the representation of the members of the Scheduled Castes Scheduled Tribes in the various central services. As the House is already aware, the UPSC as well as other recruiting agencies have been given discretion to recruit candidates belonging to these communities who may obtain lower places in competitive examinations and other selections subject of course to the minimum standards which have been laid down for efficiency. There has been an improvement in the representation of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the all-India services to a very large extent, and this has been possible particularly because we have opened one centre for pre-examination training which is useful to the members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and after taking this training at the training centre, when they appear for the competitive examinations, we get much better results from these examinations as far as the candidates from the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are concerned. Another centre has been opened in South India for this purpose. Still, we have not achieved the desired results. We would like cent per cent success for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates to fill in all the seats that are reserved for them in the various services. And this shortfall is particularly noticeable in the technical and specialised fields. I hope that with the increased facilities for advancement being given to members of such communities by way of scholarship and stipends and concessions and in the matter of admission to various institutions, more and more candidates who appear in the future examinations will succeed and we shall soon be able to fill all the quota which is reserved for these two communities.

Another important feature of the activities of the UPSC is the interviews abroad. There have been frequent references to the brain-drain from the country, and there are students who study various technical subjects abroad and unless very very special facilities are offered to them, we have been finding it difficult to attract them back to the motherland to serve here. When we started advertising the posts abroad and we started looking for these Indians and wanted to encourage them to come back to India, we found that one of the existing reasons was that it costs them very heavily to come to India for interviews at the UPSC. If they were selected, that would have been some compensation for them, but the idea in their mind would be that if they were not selected, they would be unnecessarily paying the cost of travelling to and fro. We could meet their cost of travelling in India, but the cost of their coming from countries abroad and going back would be very difficult to meet and it would be very costly. So, a system was

introduced to send either the Chairman or one of the members to countries abroad to interview candidates for such specialities for which candidates in India were not normally and easily available. This system has worked quite well and I hope we will have the endorsement of this House so that we can get more and more Indians who are taking training or serving abroad and bring them back to our country and utilise their specialized technical knowlege.

We have under consideration the question of extending this recruitment abroad to the candidates who have to be employed in various universities, the Council of Scientific and Industrial Research and the public sector concerns.

There is another important matter about which the Members might give their views and that is about the examination media of the UPSC. As you might remember, there was a proposal to introduce Hindi as an alternative media of examination in the UPSC in addition to English. After some consideration we decided that it would not be proper to introduce only Hindi as an alternative media of examination in UPSC. Then another proposal was made that we might, to begin with, introduce alternative media of examination in such languages which are already being used in various Indian univerities for the purpose of post-graduate studies. There were five to six such languages which were being used in various Indian universities for post-graduate studies, but still, we felt that it would not be proper to limit our decision only to those five to six languages. Therefore, we took a decision that the UPSC shall conduct examinations in all the languages mentioned in the Eighth Schedule of the Constitution, and candidates could take examinations in the media of those languages in addition to English. I hope that the UPSC would be able to give effect to this decision of the Government from the examinations to be held from 1968.

As hon. Members are aware, a high-powered Administrative Reforms Commission is going into various aspects of improvement in our administrative system. One of the aspects that the Commission is expected to dates in India were not normally and selection generally by the Union and State Public Service Commissions. We are looking forward to the recommendations of the Commission and I am sure that the discussion in this House will bring out a lot of useful points which could be transmitted to the Administrative Reforms Commission for its detailed consideration so that the recommendations may reflect fully and truly the feelings of the people's representatives.

There is another point which I may bring to the notice of the hon. House. That is, this Commission discharge its constitutional and statutory functions, and while we discuss the report of this Commission in the House, we might limit our discussion and criticism to the points where the Government is concerned or where the Government is answerable to this hon. House. And this will of course mean a very useful debate which will enable us to improve our working, and also enable the Administrative Reforms Commission to go into the points which hon. Members might suggest for improvement in the UPSC and their relations with the Government and *vice versa*. I am sure the Members will take care not to go into such constitutional and statutory working of the UPSC about which the Government is not responsible nor is Government answerable to this hon. House. I am sure the discussion on these points will be useful and the hon. Members will go into various points which have been mentioned in this report so that we can take appropriate action on them.

Thank you.

Shri Bibhuti Mishra (Motihari): The points mentioned in the Minis-

[Shri Bibhuti Mishra]

ter's speech are not covered in the book. A new copy should be supplied.

Shri Vidya Charan Shukla: The decisions about language media and other decisions were taken later on. But there are many points which relate to the statutory functioning of the Commission. Discussion can take place on those points and the points I have mentioned.

Mr. Deputy-Speaker: He has given further clarification with a view to invite the opinion of the House.

Motion moved:

"That this House takes note of the Fifteenth Report of the Union Public Service Commission for the period 1st April, 1964 to 31st March, 1965, together with the Government's Memorandum thereon, laid on the Table of the Third Lok Sabha on the 2nd March, 1966."

Shri R. Barua (Jorhat): What is the time allotted?

Shri Seshiyan (Kumbakonam): I suggest 5 hours may be allotted.

Mr. Deputy-Speaker: Today at 4 o'clock the Adjournment Motion will be taken up. So, this discussion will be continued later on.

Shri C. C. Desai (Sabarkantha): Sir, I would not labour this point of delay in the submission of the report to this House, although I want to mention it. I do hope that the report for 1965-66 will be submitted very soon to this House, because that report must have been submitted by the Chairman of the UPSC to the Home Ministry in July, 1966 and the Home Ministry must have taken full account of the recommendations made and the points mentioned in that report. I do hope that it will be before the House before this session ends.

Shri Seshiyan: Has it been presented to Government?

Shri C. C. Desai: The report for 1965-66 must have been submitted in July, 1966 and the report for 1966-67 must be due for submission next month. I hope all these reports would be submitted to Parliament before the current calendar year.

As the Minister said, the Commission is a constitutional organ of our parliamentary form of Government, the other two constitutional legs being the Supreme Court and the office of the Comptroller and Auditor General. Fortunately the Supreme Court has maintained its independence, integrity and high esteem in which it is held. The same thing can be said about the office of the Comptroller and Auditor General also. Three successive Auditor Generals whom I have known personally have maintained the highest tradition of that office. I also know the Chairmen of the UPSC—Mr. R. N. Banerjee, Mr. Hejmadi and Mr. B. N. Jha, whose report we are now considering. All of them have also seen the working of the Commission from the Government itself. From my experience, I can say that the traditions which have been maintained by the Supreme Court and the Auditor General have not been maintained in the relationship between the UPSC and the Home Ministry. I will give various examples of that sense of disrespect which the Ministry has for the Commission.

Looking at the personnel or the composition of the Commission mentioned in the report, one finds that there is a progressive decline in the calibre and status of the members of the commission since independence. I do not want to say anything which may mean any disrespect for any of the existing members, but judging purely from merits and comparing the personnel from time to time, you will see there is a growing deterioration in the status and calibre of the members. So much so that according to

this report, there are only 5 members working, when the sanctioned strength is 8. How is it that with the progressive increase in workload of the commission, 3 vacancies have remained unfilled? My suspicion is, there must have been some conflict between the Chairman of the commission and the Home Ministry. The recommendations of the Chairman which should have been accepted by the ministry perhaps were not accepted by the ministry because the ministry or perhaps as I know in one case the minister himself was wanting a particular person to be appointed, about whose integrity itself there was a doubt. We have to be very careful in selecting the members of the commission, because the recruitment to the highest services in the country like IAS, IFS and IPS depends on the way the commission functions. It should be the endeavour of the Home Ministry to see that the recommendation made by the Chairman for filling up the post is given the highest weight. In fact, there should be some kind of a machinery evolved—inter-State or Centre-State Council—which should go into the question of appointments to the Supreme Court and the UPSC. There have been cases where all kinds of retired people who were favourites or flatterers of the minister concerned were appointed. This is particularly so in the case of the State Public Service Commissions. At least there is some semblance of dignity in the UPSC, but I know a number of State Public Service Commissions which have been treated as nothing but dumping grounds for discredited, unwanted politicians.

The number of pending cases with the UPSC has been increasing, yet the commission has not been given the full strength of its membership. Why? The workload is increasing. They are reaching a stage like the High Courts with the number of pending cases increasing and sometimes you can find even cases 10 or 15 years old.

15.15 hrs.

[Shri C. K. Bhattacharyya *in the Chair*]

Another point is the exemption list I find all kinds of people there—Private Secretary to the Solicitor General and so on. Why are these exemptions necessary? The whole list should be re-examined and reduced to the minimum. They should go to the public service commission where there is a fair and open method of recruitment—advertisement, interview and selection on merit. If the appointments are made by the ministers or persons concerned, there is likelihood of unfairness and favouritism. To avoid this, the list should be re-examined and reduced to a minimum.

There is one system in the public service commission which I want to bring to the notice of Government. We have to interview boards for IAS and IFS. There is no common standard. One board interviews certain set of candidates and another board interviews another set of candidates. How they are going to reconcile the evaluation of these candidates is beyond me. This matter has been examined in the USA and UK and they have decided that there must be only one body of interviewers. So, I suggest it is the duty of the Chairman and at least one more member of the commission to sit on all interviews and not relegate the functions to two different boards without any common standard or method of evaluation.

One suggestion that I would like to make for improvement of the status and the respect of the Commission is in regard to the remuneration of its members. According to the original concept of the Union Public Service Commission the Chairmtn should be of the same status as Secretary to Government and members should be of the same status as Additional Secretary to Government. Since then

[Shri Sezhiyan]

this desire on the part of the ministry to overwhelm, overcome or overshadow a body like the Union Public Service Commission has induced them to lower the status of members of the Commission and reduce their salaries. This point should be examined. Now, I believe, the Chairman of the Public Service Commission gets Rs. 3,500 which is Rs. 500 less than what a Secretary to Government gets. Their status is and ought to be higher. He is a constitutional officer. Let the Chairman of the Public Service Commission remember that he cannot be removed except by a vote on the floor of this House. He cannot be removed by Government. He is a constitutional officer and his remuneration and terms of office should be proportionate to that particular esteem in which he is to be held.

They have got a system of what they call 'departmental promotion committees'. I have been a member of departmental promotion committees. I know how they have been functioning. I understand there has been some improvement since then. In my days these departmental promotion committees used to sit in the Ministry where, naturally, there was also a member of the Public Service Commission who was overwhelmed by officers of the Secretariat. Now, I believe, they have gone a step further and departmental promotion committees are held in the office of the Union Public Service Commission. But, even so, the constitution of departmental promotion committees is such that the poor member of the Commission is overwhelmed by the Secretariat representation and this is what ought to be taken care of. There should be at least two members of the Commission on every departmental promotion committee and their views should prevail as against those of the Secretariat representatives or technical people who are associated with it and who are really assessors rather than full members of the departmental promotion committee.

Secondly, they go by what they call 'confidental rolls' or 'character rolls'. I know how these character rolls are written. It depends upon the view that a particular officer takes. He writes your report according to whether he likes you or not. The Public Service Commission ought to be very careful about going into the merits of candidates and not merely relying on character rolls which are written by officers more as an expression of their own prejudice or feelings about the men under them rather than on a fair assessment of their values or work. I can give several examples. I do not want to take specific cases before the House; I would like to avoid that. If the hon. Minister wants I can tell him cases where injustices have been done or are being done on the strength of these so-called character rolls.

One complaint against the Commission, which you will find everywhere, is that there have been inordinate delays. There are 'laws delays' as the Foreign Minister said, but the delays of the Commission are even worse. This very case, this mouse of a statement that has been prepared by the Home Ministry two years after it reported to Government. Ultimately they did not accept the recommendation of the Commission to have a *de novo* inquiry simply because the case has been dragging on for four years. It is too long a period, quite true, and I agree entirely with the decision. After having put a man under trouble, under fire, for four long years we should not have a *de novo* inquiry. Where was the necessity for an inquiry for four years? Why was the departmental inquiry not completed earlier. If you are under a cloud, under suspicion, you will know what it is to pass these four years. It is like 40 years when a man has the sword of punishment hanging over his head. You should take care to see that these punishment cases are disposed of as

early as possible. They should be given priority, they should be handled quickly and the sword of punishment should not be kept hanging indefinitely for years over the head of an officer of the Government. Therefore, these delays, particularly in the matter of punishment cases or departmental action cases, should be gone into and taken care of by the Chairman of the Commission himself.

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs referred to the Administrative Reforms Commission. I do not know what exactly is the procedure followed by that Commission to go into the working of the Union Public Service Commission, but I have a suggestion to make for what it is worth. We have now three distinguished Chairmen of the Union Public Service Commission who have retired, namely, Shri Banerjee, Shri Hejmadi and Shri Jha. They can very well form a committee together with the present Chairman who is also a distinguished civilian and for whom all of us have the highest respect. If they form a committee to go into matters like the composition of the Commission, appointments, selections, membership of the Commission, working of State Public Service Commissions, how to reduce or curtail delays in departmental or punishment cases and various matters connected with it, the question of interview board to have a comparative and competitive assessment of the various candidates and so on, I am sure the Home Ministry will find ample material with which we can improve the working of the Commission and which shall give satisfaction to the whole House.

These Sir, are some of the suggestions which I had in my mind. I do hope that we shall very soon have an opportunity of discussing the 1965-66 report, which must have been presented to Government some time in July 1966, and also the 1966-67 report.

श्री रणधीर सिंह : चेयरमैन साहब सबसे पहले मैं मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने पहली बार यह प्राविजन कर दिया है कि यू० पी० एस० सी० के इम्तहान अंग्रेजी के बजाये हिन्दी और दूसरी भारतीय भाषाओं में भी हुआ करेंगे ।

एक माननीय सदस्य : "के बजाय" नहीं "के साथ साथ" ।

श्री रणधीर सिंह : मैं माननीय सदस्य का मशकूर हूं । अगर "अंग्रेजी के साथ साथ" की जगह "के बजाये" हो जाये तो बेहतर होगा ।

यह एक इनक्लाबी कदम है जो सारे देश में एक रेवोल्यूशन पैदा करेगा । अभी तक यह समझा जाता था कि हुकूमत के बड़े बड़े ओहदे ग़रीब मजदूरों, किसानों और देहात वालों के लिए नहीं हैं । गवर्नमेंट की तरफ से यह जो स्टेप लिया गया है इससे आई० ए० एस०, आई० पी० एस०, आई० एफ० एस० वगैरह बड़े-बड़े ओहदों और एजूकेशन और साइंस की बड़ी-बड़ी मुलाज़िमतों का दरवाजा ग़रीब मजदूरों, किसानों और देहात वालों के लिए खुल गया है । इस हुकूमत और मिनिस्टर साहब ने इस देश के करोड़ों इन्सानों की खुशहाली और बहबूदी की तर्जुमानी करते हुए बड़ी-बड़ी सर्विसिज़ में उनको नुमायन्दगी देने के लिए यह जो कदम उठाया है उसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं ।

इस वक्त इन इम्तहानों के सेंटर दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता वगैरह पांच सात बड़े-बड़े शहरों में होते हैं । मिनिस्टर साहब बराये मेहरबानी यह इन्तजाम भी कर दें कि हरियाणा जैसी छोटी-छोटी स्टेट्स में, रोहतक वगैरह जगहों में, इन इम्तिहानों के सेंटर खुलवा

[श्री रणधीर सिंह]

किये जायें ताकि ग़रीब आदमियों को बहुत पैसा खर्च करके इम्तहान में बैठने के लिए इन बड़े-बड़े शहरों में आने की जहमत न उठानी पड़े, बल्कि वे थोड़ा सा पैसा खर्च करके अपने करीब के शहरों में इम्तिहान में बैठ सकें। इन शहरों के कालेजों या दूसरे इंस्टीट्यूट्स में सेंटर कायम किये जायें ।

अभी तक आई० ए० एस० और आई० पी० एस० के ओहदे कुछ खानदानों का ठहवारा, उनकी मानोपली बने हुए थे । उन खानदानों के लोग ही इन ओहदों पर आते थे और वे इस मुल्क की आरिस्टोक्रेसी और ब्यूरोक्रेसी बन गए थे । गवर्नमेंट ने जो यह नया कदम उठाया है इसकी बदौलत ग़रीब किसानों, मजदूरों और देहातियों के बच्चे भी इन ओहदों पर आया करेंगे ।

इस बात का भी ध्यान रखा जाये कि जो लोग इन ओहदों के लिए भर्ती किये जायें वे कुछ ग़रीबनवाज, देहातनवाज रूरल-माइंडिड लेबर माइंडिड, और शामिलातारी के हमदर्द हों ।

मैं यह नहीं कहता कि अनपढ़ आदमियों को आप वहां बिठा दें, लेकिन ग़रीब के लिए जिसके दिल व दिमाग में हमदर्दी हो उसको मेम्बर बनाइए और मैं इस बात के खिलाफ़ नहीं हूं कि एक्सपर्ट्स को वहां भेजा जाये । एक्सपर्ट्स को भेजिये लेकिन जो टाई वाले, हैट वाले और इंग्लिस्तान और दूसरे देशों की कापी जो करते हैं जो रिजर्वनेस को मैरिट का क्राइटीरियन समझते हैं और कहते हैं कि हम तो प्योरली आन मैरिट आते हैं इस तरह की मैरिट का क्राइटीरियन रखने वाले को न भेजिये । भर्ती करने के लिए एक बैलेंस है लड़का इम्तिहान में तो आ जाता है पास कर लेता है टेस्ट को, लेकिन जब वहां जाता है तो कालर ठीक नहीं है, बाल ठीक नहीं है, टाई ठीक नहीं है, जूते में पालिश नहीं है, इस बात के नम्बर मिलते हैं जब कि नम्बर मिलना चाहिए इस बात के कि कितने ग़रीब घर का है, किसान का लड़का है या नहीं, देहात में काम किया है या नहीं, कम्यूनिटी डेवलपमेंट में काम किया है या नहीं या ग़रीब हरिजन का छोटे मुलाजिम का लड़का है या नहीं, इस बात के नम्बर मिलने चाहिए। अब वह बात खत्म हो गई कि हमारा बाप डिप्टी कमिश्नर था या आई० सी० एस० था या रेलवे कमिश्नर था यह बातें खत्म हो गईं। बहुत दिनों तक बड़े बड़े ओहदेदारों जागीरदारों और ताल्लुकेदारों ने आई० सी० एस०, आई० ए० एस०, आई० एफ० एस० आदि बड़ी-बड़ी नौकरियों पर अपना कब्जा बना कर रखा। उन का यह किला अब टूटना चाहिए । हमें पता है बड़ी बड़ी सर्विसेज का हाल । मैं कोई तौहीन नहीं करता मगर यह कहना चाहता हूं कि मिनिस्टर साहबान तो हैं लेकिन हुकूमत फिर भी बड़े बड़े अफसरान ही करते हैं । यह नीचे से लेकर ऊपर तक, चलता है। आज कैबिनेट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, ऐडीशिनल सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और पता नहीं कितने सेक्रेटरी हैं जो देश को गवर्न करते हैं। यह पार्लियामेंट या मिनिस्टर या हमारी गवर्नमेंट को खामख्वाह लोग बदनाम करते हैं असल हुकूमत तो यह अफसरान ही करते हैं।

तो मैं यह कहना चाहता हूं कि रूरल माइन्डेड, रूरल ओरिएन्टेड सेलेक्शन बोर्ड बनाएं। साथ के जो क्वालिफिकेशन्स हैं वह भी एक स्कोप अपना बनाएं कि उन आदमियों या उन लड़कों को खास तौर पर सेलेक्ट करें जिन्होंने देहात में काम किया है, जो मजदूरों के, ग़रीबों के, किसानों के लड़के हैं। चाहे वह एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, जितने भी महकमे हैं उन में उन को प्रेफ़र किया जाए जो खास तौर पर

गरीब हैं और देहात में जिन्होंने काम किया है।

दूसरी बात शिड्यूल्ड कास्ट का रिजर्वेशन आप ने कर दिया। बहुत अच्छा काम किया। परमात्मा आप का भला करे। लेकिन एक बात और कहना चाहता हूं कि शिड्यूल्ड कास्ट के कमिश्नर की रिपोर्ट मैंने पढ़ी है। उन की शिकायत तो है कि रिजर्वेशन तो हर जगह आप लिख देते हैं लेकिन सेक्शन में वह जगह हमेशा खाली ही पड़ी रहती हैं। लिया कोई नहीं जाता। मैं दरख्वास्त गुजारिश करूंगा कि वह जगहें जो हरिजनों के लिए हैं, गरीबों के लिए हैं वह पूरी की जायें और हरिजनों में से पूरी की जायें, ऐसा न हो कि अगले साल करेंगे, इस से अगले साल करेंगे, वह भरी नहीं जातीं, यह बड़ी भारी शिकायत है और यह मेरी शिकायत नहीं है जो कमिश्नर हैं, हरिजन वेलफेयर कमिश्नर, शिड्यूल्ड कास्ट के, उन की रिपोर्ट है और गवर्नमेंट से शिकायत है कि वह जगहें फिल नहीं होतीं। तो जितनी भी ऐसी जगहें हैं जो फिल नहीं होतीं वह फिल की जायें।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि कई स्टेट्स में पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ एक सेलेक्शन बोर्ड आर्डिनरी सर्विसेज के लिए भी बनाया गया है जैसे मेरे पंजाब में था और बड़ा अच्छा काम उस ने किया। सेंटर में शायद नहीं है। तो सेंटर में भी एक ऐसा बोर्ड आप कायम क । आफिसर्स के डिस्क्रिशन पर न छोड़ें कि कोई चीफ इंजीनियर है तो अपने रिश्तेदारों को ही भर्ती करता चला जाता है, बहू का भांजा कौन है, साले का ससुर कौन है, यह मैं कोई किसी की जाती की बात नहीं कर रहा हूं लेकिन यह असलियत है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में कि एक बड़ा अफसर हो जाता है तो अपने नजदीकी रिश्तेदारों को भर्ती करना शुरू कर देता है। इसलिए एक सेलेक्शन बोर्ड बनाइए जैसे कि एस० डी० सी० या यू० डी० सी० हैं, उन के लिए। मेरी शिकायत है कि गरीब आदमी, हरिजन और किसान उनको आई०सी० एस० और आई० एफ० एस० कौन बनाए वह छोटे मोटे डिपार्टमेंट्स के अन्दर चपरासी बनते हैं, एल० डी० सी० और यू० डी० सी० बनना भी उन के लिए बड़ा मुश्किल है। हमें पता है मामूली सी जगह पर भर्ती के लिए दिल्ली और दूसरी जगहों में क्या-क्या करना पड़ता है, वह मैं कहना नहीं चाहता हूं, शायद वह इस हाउस की शान के खिलाफ होगा। दूसरी बात यह कि इस से करप्शन भी बढ़ता है। मैं नाम नहीं लेता किसी अफसर का लेकिन यह सही बात है अगर आप चाहें तो मैं मिसाल दे सकता हूं कि यह छोटी-छोटी नौकरियां बाकायदा बिकती हैं दो दो सौ, चार चार सौ, छः छः सौ रुपये एक मामूली सी पोस्ट के लिए देने होते हैं। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन की एफिश्येंसी और कांग्रेस हुकूमत की रेपुटेशन के लिए कहना चाहूंगा कि छोटी नौकरियां जो उन के लिए भी एक छोटा सा सबार्डिनेट सर्विसेज सेलेक्शन बोर्ड रखें। और कम्पीटीशन रख दीजिए। उस से फायदा होगा कि गरीब का बच्चा भी छोटी छोटी नौकरियों में कम से कम आ सकेगा और फिर तरक्की करते करते और ऊपर पहुंच जायगा।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो मेम्बर हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के इन को पूरी आटोनामी दी जाये। जो एक दफा मेम्बर है वह फिर गवर्नमेंट सर्विस में न आये, रिटायर ही हो जायें। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा लेकिन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के मेम्बर हैं जो गवर्नमेंट सर्विस में चले गए। यह तो इतनी सैटिस्फाइड जगह है कि वहां से फिर गवर्नमेंट सर्विस में कभी नहीं जाना चाहिए। वाइस चांसलर बन जाये उस को भी मैं इसी में समझता हूं... .... (व्यवधान) ....तो देसाई साहब ने ठीक

[श्री रणबीर सिंह]

बात कही, मैं उस से सैंट परसेंट एग्री करता हूं कि अच्छा तो जो इतने आटोनामस बोर्ड्स हैं इनमें एक्सपर्टस आने चाहिए। यह बात दूसरी है कि भलेमानसों को रखें जो गरीब का और देहात का भला चाहने वाले हों। जो टाई या हैट वालों को अफसरी के लायक समझते हैं, उन को न लिया जाये। उस के बाद जो वहां अप्वाइंट हो जाये वह फिर किसी का डर न माने, होम मिनिस्टर का डर न माने, प्राइम मिनिस्टर का डर न माने, प्रेसीडेंट का डर न माने, अपनी कांशेंस से काम करे और फिर वहां से वह रिटायर हो जाये। इस से गवर्नमेंट का नाम भी ऊंचा होगा, इन्टेग्रिटी बढ़ेगी और वह परमात्मा को हाजिर नाजिर समझकर अपने दिल से काम करेगा।.....

.....(व्यवधान).....यहां तो ठीक है लेकिन मैं पंजाब की बताता हूं.....

श्री विद्याचरण शुक्ल : पंजाब से यहां मतलब नहीं है।

श्री रणबीर सिंह : मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसे मेम्बर्स हैं जो मेरी पार्टी के भी हैं, अच्छे भी हैं लेकिन क्यों ले लिए? मैं इस प्वाइंट का हूं कि वह आदमी लीजिए जो पोलिटिकल प्यूज के न हों।

तनख्वाह की बात जो देसाई साहब ने कही मैं उस से एग्री नहीं करता. इतनी तनख्वाह नहीं देनी चाहिए। वह कहते हैं कि यह तनख्वाह थोड़ी है, दो हजार, तीन हजार या चार हजार। मैं यह कहना चाहता हूं कि देश बहुत गरीब है। जो बिमी कि रिटायर होने को है वह रिटायर होने के पहले थोड़े दिन यहां काम करे और आनरेरियम पर काम करे, गरीब आदमियों की खाल न उतारे और बड़ी तनख्वाहें न ले। जिस आदमी को रिटायर होना है वह छोटी तनख्वाह ले। तो मैं यह सुझाव दूंगा कि वह एक्सपर्टस साइंस वाले या एग्रीकल्चर वाले या किसी भी विषय के लीजिए लेकिन वह आदमी लीजिए जो कि आन दि वर्ज आफ रिटायरमेंट हो या रिटायर हो गया हो। कुछ अपने ला में तब्दीली करें। थोड़ी तनख्वाह पर उसे रखें और वह अप्वाइंट होने के बाद आपसे दब न।

एक बात आपने बाहर जाने के बारे में फरमाई, क्योंकि टैलेन्ट्स अगर यहां बुलाया जायेगा, तो उसमें खर्च ज्यादा होगा। इस बारे में मैं अर्ज करना चाहता हूं कि क्या वजह है कि हमारे देश के तीस-चालीस हजार साइन्सदान ऐसे हैं, जो देश में आना पसन्द नहीं करते, बाहर ही रहना चाहते हैं। अगर कोई आता भी है, तो 6 महीने के बाद फिर भाग जाता है। वे यहां क्यों नहीं आते? मुझे बताया गया है कि वे यहां आना चाहते हैं, लेकिन वे अपने आप को यहां एडजस्ट नहीं कर पाते। अगर किसी को वहां एक हजार रुपया मिलता है, तो तो वह यहां पर तीन सौ रुपये में आने को तैयार है, लेकिन उनके साथ ठीक ट्रीटमेंट नहीं किया जाता, इस वजह से वे लोग यहां नहीं आना चाहते। वहां का वे-आफ-बिहेवियर कुछ और है, प्रिन्सिपल आफ कांडक्ट कुछ और है, जब कि यहां पर उन को रगड़ा दिया जाता है, उन को काम करने का मौका नहीं दिया जाता है। जब तक बड़े अफसर यह नहीं समझेंगे कि नौजवान लड़के हमारे अपने बच्चे हैं, जो हजार रुपये की नौकरी को छोड़कर देश की सेवा करने के लिये 300 रु० पर यहां आये हैं, जब तक उनको देश की दौलत नहीं समझेंगे, उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं देंगे, तब तक वे यहां नहीं आना चाहेंगे। आज हमारे आफिसर यह समझते हैं कि ये नौजवान लड़के जो कि बहुत टैलेन्टेड हैं, थोड़े अरसे के बाद उनकी जगह ले लेंगे। हमारे देश में टैलेन्ट्स की कमी नहीं है—डा० नार्लिकर भी एक ऐसा ही नौजवान है जो थोड़े से वर्षों में दुनिया का

बदस्तूर सायन्सदान हो गया है—25 साल का लड़का है—लेकिन वह भी छोड़ कर चला गया। मेरे गांव का एक लड़का है, एक निहायत गरीब किसान का लड़का, जिसके पास सिर्फ एक बैल है, उसने अमरीका से पी० एच० डी० किया और वहां के 65 साल के रिकार्ड को बीटर किया, वह लड़का यहां आ गया है। उस को ठीक तनख्वाह नहीं मिलती थी, हमने कहा कि तुमको देश को छोड़ कर नहीं जाना चाहिये। एक और लड़का मेरे हल्के का है जो बड़ा भारी डाक्टर है, तीन महीने मुलाजमत करने के बाद कहता है कि मुझसे मुफ्त काम करा लें, लेकिन यहां पर ठीक ट्रीटमेंट नहीं होता है।

मेरे एक दोस्त चीफ-इंजीनियर ने मुझे यह बतलाया कि यहां के तमाम बड़े बड़े महकमों में आई०सी०एस०, आई०ए०एस० आफिसर्ज हेड हैं, लेकिन यह जरा सोचने की बात है कि इर्रिगेशन के महकमे में किसी अफिसर को हेड बनाना, या इंजीनियरिंग के महकमे में किसी अफिसर को हेड बनाना कहां तक मुनासिब है, किसी आई०सी० एस० आफिसर को इन महकमों का हेड बनाना एक हिमाकत है, बेवकूफी है। मैं यह बात कह रहा हूं जो देश के हित की है, एडमिनिस्ट्रेशन के हित की है और हमारी पार्टी के लिये हित की बात है जो आदमी सायन्सदान है, या जिन्होंने अपनी सारी उम्र बड़ी बड़ी डिग्रियों को हासिल करने में लगा दी है, उनके ऊपर 20-25 साल के लड़के को, जिसने आई० ए० एस० कर लिया है, उसको सेक्रेटरी बना कर बैठा देना, कहां तक मुनासिब है। आप मेरी बात को एप्रीशियेट कीजिये—ये लड़के जो देश का दिमाग हैं, जो बाहर फिरते हैं, जो अमरीका और इंगलैंड में डिसेटिसफाइड हैं, जो देश में आना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, देश भक्त हैं, इस वास्ते नहीं आना चाहते, क्योंकि वे हमारे अफसरान से डरते हैं, क्योंकि हमारे अफसरान टैलेन्ट्स को अच्छी तरह से एप्रीशियेट नहीं करते, उन को एकमोडेट नहीं करना चाहते। मैं होम मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं, मुझे पता है कि आप नौजवान हैं, आप इस बात को देखेंगे कि इन टैलेन्ट्स के लिये आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आपकी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को अमरीका, इंग्लैंड जाने की जरूरत नहीं है, हमारे ये टैलेन्ट्स झुण्ड के झुण्ड यहां आने को तैयार हैं, बशर्ते कि आप उन के लिये यहां अच्छा एटमोस्फियर क्रियेट कर दें।

महोदय, मैंने बहुत टाइम लिया है, जितनी बातें मैंने कही हैं अगर कोई गलती की हो, तो मैं उसके लिये क्षमा चाहता हूं।

श्री श्रीचन्द गोयल (चण्डीगढ़): चेयरमैन साहब, इस समय इस सदन के सामने लोक सेवा आयोग की 15वीं रिपोर्ट है। मैं समझता हूं कि लोक सेवा आयोग लोकतंत्र को कायम रखने के लिये जो चक्कर बड़े पाये हैं, उन में से एक है। एक पाया न्यायालय है, दूसरा पाया आडिटर तथा एकाउन्टैन्ट जैनरल है, तीसरा चुनाव कमीशन है और चौथा पाया यह लोक सेवा आयोग है। इस लिये मैं समझता हूं कि हमारे लोकतंत्र में इसका बहुत बड़ा महत्व है। इस लिये आज हमें विचार करना चाहिए कि इसके अधिकार से आज जो पोस्टें निकाली जा रही हैं, जो इस रिपोर्ट में एक लम्बी चौड़ी फेहरिस्त दी गई है, जिसमें अनेकों प्रकार की सेवाएं इसके अधिकार से निकाली गई हैं, यह कहां तक मुनासिब है। पब्लिक अण्डर टेकिंग्ज के सम्बन्ध में जो रिपोर्ट आई थी, उसको देखकर हमें मालूम हुआ कि इन में सेवाओं को प्रायः उन लोगों से 'भर्ना' किया गया है जो कि सर्विस से रिटायर हो चुके हैं — इसका अर्थ यह हुआ कि पब्लिक अण्डर टेकिंग्ज में

[श्री श्रीचन्द गोयल]

भर्ती करते समय उचित नियमों का पालन नहीं किया जाता और जिसका नतीजा है कि एक दो को छोड़ कर शेष सभी पब्लिक अण्डर टेकिंग्ज सिफारिश के, चाटे के कारण बने हुए हैं । मैं चाहता हूं कि इन संस्थाओं में भी भर्ती के लिये, तरक्की के लिये या रिटायरमेंट के जो नियम हैं, उन का ठीक तरह से पालन होना चाहिये। तथा लोक सेवा आयोग की देख रेख में यह होना चाहिये।

इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं का सम्बन्ध है, और जिसके बारे में होम मिनिस्टर साहब ने यह प्रश्न भी उठाया है और उन्होंने कहा है कि इस सदन के जो सदस्य इस सम्बन्ध में अपनी राय दें। मैं समझता हूं कि सरकार की ओर से उचित पग उठाया जा रहा है। अंग्रेजी भाषा के साथ साथ लोक सेवा आयोग की परीक्षायें भारत की सभी भाषाओं में होनी चाहियें। इसकी शुरुआत हिन्दी से हुई है, लेकिन आज देश में अनेकों इस प्रकार के विश्वविद्यालय हैं, जिन्होंने अपनी क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से वहां शिक्षा देना आरम्भ किया है। मैं समझता हूं इसके लिये इस बात की आवश्यकता होगी कि एक टैक्नीकल टर्म्स की डिक्शनरी बनाई जाये तथा उसी के अनुरूप कोर्सेज की व्यवस्था करें, चूंकि यह एक माना हुआ सिद्धान्त है कि एक विद्यार्थी अपनी भाषा के अन्दर, मदर-टंग के अन्दर अपने विचारों को जिस प्रभावी ढंग से प्रकट कर सकता है, वह अंग्रेजी भाषा में नहीं कर सकता, विदेशी भाषा को दस दस पन्द्रह पन्द्रह साल तक सीखने में समय लगाने के बाद भी वह योग्यता प्राप्त नहीं कर सकते, जो अपनी मातृभाषा में कर सकते हैं, इस लिये आज लोक सेवा आयोग को अपनी सभी परिक्षायें भारत की सभी भाषाओं में करनी होंगी अतः इस दिशा में हम जितनी जल्दी पग उठा सकें, उठायें यह देश के लिये अतिआवश्यक है, देश के हित में है।

इस के साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस रिपोर्ट में जो एपेन्डिक्स 9 है, उसमें 163 ऐसे केसेज की सूची दी गई है, जिसमें यह बताया गया है कि कमीशन को योग्य प्रत्याशी, योग्य उम्मीदवार प्राप्त नहीं हुये । इस लिये उन सेवाओं की आवश्यकता होते हुए भी आयोग योग्य उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश नहीं कर पाया । यदि आप इस सूची की छानबीन कर के देखेंगे तो आप आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि इसमें बहुत से ऐसे केसेज हैं, जिनमें किसी खास टैकनिकल ज्ञान की आवश्यकता नहीं थी । इस में कुछ भाषा के केसेज हैं, शिक्षा के हैं, कालेज के प्रिन्सिपल्ज के केसेज हैं, मिलिट्री या दूसरे विभागों के केसेज भी हैं। मुझे इसमें दो दोष दिखाई देते हैं। एक तो यह कि जिस समय इन स्थानों के लिये कोई क्वालीफिकेशन या स्पेसिफिकेशन तय करते हैं, उस समय सरकार के विभाग में कोई न कोई व्यक्ति होता है। मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि सेवाओं में आज भाई-भतीजावाद या नैपोटिज्म भी सरायत कर चुका है । हम देखते हैं कि एक विभाग का एक व्यक्ति अपने ही प्रदेश के लोगों को भरती कर प्रान्तीय वाद का परिचय देता है, सेवाओं की भरती योग्यता के आधार पर नहीं की जाती। इसलिये मैं यह समझता हूं कि या तो क्वालीफिकेशन्ज या स्पेसिफिकेशन्ज तय करते समय हमारे विभाग में कुछ उम्मीदवार रहते हैं, जिनको देख कर हम क्वालीफिकेशन्ज तय करते हैं या मैं समझता हूं कि इसका दूसरा कारण यह हो सकता है कि हम इस प्रकार का वेतन उनको नहीं देते, आकर्षक

इमौलूमेंट्स उन को नहीं देते, जिससे कि हम देश की टैलेन्ट्स को, देश की प्रतिभा को आकर्षित कर सकें। यही कारण है कि हम उन स्थानों को पुर नहीं कर पाते। आज जब देश में इतनी यूनिवर्सिटीज कार्य कर रही हैं, आज जब देश में इतनी बेकारी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, जब इतने विद्यार्थी विदेशों से शिक्षा प्राप्त करके यहां आ रहे हैं, तब क्या कारण है कि हमें इन 163 स्थानों के लिये योग्य उम्मीदवार नहीं मिल सके। इस लिये हमें या तो क्वालीफिकेशन्स के अन्दर कुछ परिवर्तन करना होगा या हमें उनको बेहतर वेतन देने होंगे ताकि हम देश की प्रतिभा को इस दिशा में आकर्षित कर सकें।

सभापति महोदय, इस के साथ साथ मैं आप का ध्यान एपैंडिक्स 13—14 की तरफ भी दिलाना चाहूंगा। एपैंडिक्स 13—14 के अन्दर सफ़ा 77 के ऊपर उन केसज की सूची दी गई है जिनके अन्दर हम ने एक परीक्षा के लिए एडवरटिजमैंट किया और उस के बाद इंटरव्यु से पहले ही हमने यह कह दिया कि अब यह पोस्टें कैंसिल की गई हैं। ऐसे भी केसेज दिये गये हैं जिनके अन्दर ऐडवरटिजमैंट करने के बाद और इंटरव्यू लेने के बाद हम ने उन पोस्टों को कैंसल कर दिया। अब सभापति महोदय आप विचार कीजिये कि लोकसेवा आयोग को एक ऐडवरटिजमैंट करने के लिए कितना खर्चा करना पड़ता है और प्रत्याशी को उस के लिये कितना खर्चा करना पड़ता है? एक परीक्षा लेने के लिए सरकार और उस में बैठने वाले प्रत्याशियों को कितना रुपया खर्च करना पड़ता है? विशेष कर इंटरव्यू लेने के बाद उस पोस्ट को कैंसिल कर देना मुझे उस में कोई माकूलियत नजर नहीं आती। मेरी समझ में इस दिशा में सुधार करने की आवश्यकता है। पोस्ट्स को ऐडवरटाइज करने से पहले परीक्षा लेने से पहले यह देख लिया जाय कि वाकई उस की आवश्यकता है या नहीं और आवश्यक महसूस होने पर ही उस को ऐडवरटाइज किया जाय लेकिन इस तरह से कि इम्तिहान ले लिया और इंटरव्यु भी ले लिया और फिर पोस्ट को कैंसिल कर दिया यह उचित बात नहीं है।

एपैंडिक्स 15 के अन्दर 171 ऐसे केसेज की सूची दी गई है जिनमें लोकसेवा आयोग की सिफारिश करने के दो, दो साल बाद भी उन पोस्टों को भरा नहीं जाता है। अब जो उम्मीदवार है और जिनके कि नाम की सिफारिश लोकसेवा आयोग ने की हुई होती है उन के दिमाग पर क्या गुजरता होगा। इस प्रकार के केस जिनमें कि लोकसेवा आयोग ने सिफारिश की हुई है लेकिन उनको बुलाया नहीं गया है ऐसे बीसियों केस हैं। रिपोर्ट में यह लिखा हुआ है कि लोकसेवा आयोग ने उन के नामों की सिफारिश सम्बन्धित विभागों को कई साल पहले से की हुई है लेकिन अभी तक उन की नियुक्ति नहीं हुई। आखिर लोकसेवा आयोग अपनी ओर से तो यह परीक्षाएं और इंटरव्यु आदि नहीं करता है। सरकारी विभाग द्वारा उन पोस्ट्स की मांग की जाने पर ही वह यह पोस्ट्स ऐडवरटाइज करता है तो फिर आखिर नियुक्ति में इतनी देरी किस कारण होती है कि वह लोकसेवा आयोग की सिफारिश के बाद भी दो, दो साल रिक्त स्थानों की पूर्ति नहीं हो पाती है। और सम्बन्धित विभागों द्वारा प्रत्याशियों को पोस्ट्स पर कौल नहीं किया जाता है? मेरी राय में यह पबलिक सर्विस कमिशन और उन व्यक्तियों के साथ ज्यादती है जोकि बुलाये नहीं जाते हैं। कमिशन की उन्हें लिये जाने की सिफारिश के बावजूद भी दो, दो और तीन, तीन साल तक उन को नहीं लिया जाता और उन को इस बात से भी वंचित किया जाता है कि वह किसी दूसरे विभाग में या किसी दूसरे महकमे के अन्दर सेवा प्राप्त कर सकें।

इस के साथ साथ मैं पिछले वर्षों के उम्मीदवारों के सम्बन्धों में कुछ निवेदन

[श्री श्रीचन्द गोयल]

करना चाहूंगा कि होम मिनिस्टर साहब ने भी यह पूछा है कि इस सम्बन्ध में मैम्बरान की क्या राय है ? मैं समझता हूं कि जो शेड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के विद्यार्थी हैं उन्हें जो रियायत मिलती है वह रियायतें कायम रक्खी जायें । अभी तक इस प्रकार की स्थिति नहीं आई है कि शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेयूड्ल्ड ट्राइब्स से सम्बन्ध रखने वाले जो प्रत्याशी या विद्यार्थी हैं वह बाक़ियों के स्तर पर नहीं आ सके हैं । उन की योग्यता का स्तर आज भी अनेकों कारणों से सवर्ण जाति वालों की तुलना में पीछे है । इसलिए जिस प्रकार से हम ने लोकसभा या विधान सभाओं के चुनाव लड़ने में रिजर्वेशन रखी है उसी प्रकार से लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में भी रियायतें शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के विद्यार्थियों को हमें देने होंगी और तब तक देनी होंगी जब तक उनकी योग्यता का स्तर बाकी विद्यार्थियों के स्तर पर न जाय ।

मैं एक आखिरी बात कह कर समाप्त कर दूंगा । एक और बात की तरफ होम मिनिस्टर साहब ने तवज्जह दिलाई है । उन्होंने कहा है कि जो विद्यार्थी विदेशों के अन्दर पढ़ते हैं और उन को हम भारत के अन्दर लाना चाहते हैं और उनको योग्यता के आधार पर उन को उपयोग करना चाहते हैं उस के लिए मैं समझता हूं कि यह उचित बात है कि बजाय इसके कि उन विद्यार्थियों को भारत में बुला कर इंटरव्यु लिया जाय, लोकसेवा आयोग के ये रमै। या अन्‍ सदस्य उन्हीं देशों में जाकर इंटरव्यु कर लें । इस के लिए दूसरे देशों में ऐसे, दो चार विशेष केन्द्र बनाये जा सकते हैं जिन केन्द्रों पर उन सभी विद्यार्थियों को बुला कर उन का इंटरव्यु ले लिया जाय ताकि उन विद्यार्थियों को इतनी दूर भारतवर्ष में इंटरव्यु के लिए न आना पड़े ।

Shri P. Ramamurti (Madurai): I am afraid that I have very little time before four o' clock today and so I have to finish my speech today; I am afraid that I shall not be able to continue my speech the day after tomorrow. Therefore, I shall try to pinpoint the attention of this House on one point.

It is now stated that Government recruit people without any fear or favour through an independent authority called the Public Service Commission. But I would like to point out that this loses all meaning whatsoever since after recruitment Government seek power, and through a directive to all the States ask them, to get the antecedents of the people who are recruited to Government service verified by the police. They have listed a number of political parties, none of which has been banned under the Constitution. All those parties are constitutional parties functioning inside this country perfectly within the four corners of the Constitution. But by means of the Home Ministry's directive Government have taken powers to cancel the appointment of those people who are supposed to owe allegiance to some political parties, on the basis of the report of some Tom, Dick and Harry in the police force, an ordinary constable, who comes and says that this man had had something to do with the Communist Party, or the DMK or some other political party. I would like to ask Government whether they have got any morality in doing this kind of thing. After all, under the Constitution, every party can function in this country, and it is up to the people of this country to elect any party to power. Today, the Congress Party may be in power at the Centre, and tomorrow, it may be thrown out of office and some other party may come to power. Today, for example, in a number of States, non-Congress parties are in power. In Kerala, for example, the Chief Minister happens to be a member of the

Communist Party, namely our party. The moment we come to power in Kerala, the moment any party comes to power in Bengal, the moment another party comes to power in Madras, should we ask the police to go and verify the antecedents of those persons who have had anything to do with the Congress Party and then say that all those persons who have had any connection whatsoever with the Congress Party will be denied of Government service? What does it mean? I want to point out that the Congress Party, having been in power all these years, has been utilising the power and misusing the power in order to strike terror in the minds of the people. It is a kind of terrorisation which they have indulged in in order to get support for themselves. The Congress Party has been seeking to strike terror in the minds of the people by saying, 'Look here, if you have got anything to do with such and such a party, you will not be given any jobs, your kith and kin will not be given jobs, your sons and daughters will not be given jobs, and, therefore, keep away from such and such a party.'. This is the way in which the Congress Party has been functioning all these twenty years. But we do not do any such thing when we are in power. Today, for example, it is open to us in Kerala, it is open to us in Bengal, to pass an order asking the police to go and verify the antecedents of all the Government servants and then say that if anybody has got anything to do with the Congress Party he will not be given any jobs.

An hon. Member: You may do it.

Shri P. Ramamurti: We are not such type of people; we are not such mean-minded people. We do not seek to get the support of the people by terrorising the people of this country; but we seek to get their support on the basis of our programmes and on the basis of our service to the people. So, we are not afraid of this kind of thing.

Within the short time at my disposal I do not want to deal with the other questions raised by the report of the Commission. The main thing that I would like to pin-point and to which I would like to draw the attention of the Government and the House is that it is high time that the Home Ministry withdraws its circular and respects the Constitution about which the Government are shouting so much. They come and taunt the Opposition parties and ask them 'Do you believe in the Constitution?'. I would like to ask them whether they have got faith in the Constitution. If they have faith in the Constitution, they should allow the citizens of this country to owe allegiance to any party which is constitutionally allowed to function in this country within the four corners of the Constitution. So long as they do not allow that, so long as they seek to strike terror in the minds of the people, the only thing that can be said is that there is a party which is not sure of its support from the masses of the people and which knows that day after day it is losing the support of the people. Gone are those days when the people of this country trusted the Congress leaders and were willing to take the word of the Congress Party.

Today the people do not trust them. The people do not trust the Congress leaders. The Congress leaders' exhortations do not carry conviction with the mass of the people. Being faced with this situation, the Congress Party seeks to prepetuate itself in power by striking terror.

16 hrs.

So I would make this appeal. It is high time they learnt their lessons. In this way, they cannot get the support of the people. The people will certainly rise against this kind of terrorisation. Any kind of terrorisation of the people will not cow them down. Once the people are determined to take their destinies in their own hands, any amount of this kind of terrorisation will not cow them

[Shri P. Ramamurti]

down. Therefore, it is high time they learnt the lesson of the past 20 years and immediately withdrew this circular before attempting to parade the Public Service Commission's Report before the people and telling the world that they are very impartial in recruiting people, that they have got an independent authority which goes into the whole question. Let us not have anything more of this kind of humbugging of the people, because it is nothing but downright humbug.

Mr. Chairman: The debate on this motion is adjourned and will be resumed after the disposal of the adjournment motion. The adjournment motion will continue till 6 P.M. Then this can be taken up either today or the day after tomorrow.

16.02 hrs.

MOTION FOR ADJOURNMENT

FOOD SITUATION IN THE COUNTRY

Mr. Chairman: The House will now take up the motion for adjournment. The Mover may take 15 minutes and other members 10 minutes each.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): Before I move my motion, may I request you to kindly see the rules? Under the rules, 2½ hours should be the minimum; it is not the maximum. Since this is a very major problem, one of the most vital problems before us, I shall be doing injustice to myself and to the people of this country if I am unable to cover certain points. So I would request you to extend the time; the Mover may have 25 minutes and other members may have 15 minutes each. So if the House agrees, the time should be extended.

Shri Sezhiyan (Kumbakonam): The minimum is prescribed, not the maximum.

The 2½ Hours prescribed is the minimum.

Shri S. M. Banerjee: I am prepared to sit longer, till 7 P.M.

Mr. Chairman: Let me ascertain the wish of the Minister.

The Minister of Parliamentary Affairs and Communications (Dr. Ram Subhag Singh): It should be finished by 6 P.M.

Mr. Chairman: It will continue till 6 P.M.

Shri Indrajit Gupta (Alipore): Then it is a violation of the rules, because the rule says 2½ hours.

Shri P. Ramamurti (Madurai): Then are we continuing the adjournment motion the day after tomorrow, because upto 6 P.M. it is only 2 hours whereas the minimum prescribed is 2½ hours? Let us continue it the day after tomorrow.

Mr. Chairman: Is it the sense of the house that the debate may continue upto 6.30 P.M.?

Some hon. Members: Yes.

Shri S. M. Banerjee: Rule 62 says.....

Mr. Chairman: I have read the rule. It is better that he proceeds with his main speech.

Shri S. M. Banerjee: I move:

> "That the House do now adjourn".

Mr. Chairman, this morning, in reply to a call attention notice, the hon. Minister of Food and Agriculture laid a statement on the Table in which he has tried to convince the House that 'the food situation in the country continues to be difficult.' He further said:

> "The internal production has suffered badly as a result of two successive years of drought".